भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2174

जिसका उत्तर दिनांक 22 अगस्त, 2013 को दिया जाना है।

आटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी

2174. श्री दत्ता मेघे:

श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दशक भर में कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री अपने निम्नतम स्तर तक आ पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों को रोजगार विहीन होने और इस उद्योग/सरकार को राजस्व में कितनी कमी होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त उद्योग को कोई पैकेज देने तथा इसके कारबार/लाभार्जन को सुधारने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क) और (ख) : जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों में यात्री वाहनों की बिक्री बढ़ी है। पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में कुछ कमी आई है। अप्रैल 2013 से जुलाई 2013 में यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में क्रमश: 7.49% और 9.91% की कमी आई। यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री का ब्यौरा निम्नवत है:-

ऑटोमोबाइल घरेलू बिक्री प्रवृत्तियां

श्रेणी	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**अप्रैल-जुलाई (2013-14) % परिवर्तन**
यात्री वाहन	2,501,542	2,629,839	2,686,429	7,93,708 (-7.49%)
वाणिज्यिक वाहन	684,905	809,499	793,150	2,33,634 (9.91%)

(ग), (घ) और (ङ) : उद्योग सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श से सरकार ऑटो सेक्टर के व्यापक और सतत् विकास के लिए बहुत से उपाय करती है। इस संबंध में, सरकार द्वारा उद्योग सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहन परामर्श के बाद **ऑटो मिशन प्लान 2006-16** तैयार किया गया है। यह मिशन प्लान इस सेक्टर के लिए सरकारी नीति की आधारशिला है। इसके अतिरिक्त, देश में इस सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई पहल की गई हैं; जैसे **ऑटो सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी)** का गठन, होमोलोगेशन और टेस्टिंग के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना की स्थापना के लिए 2288 करोड़ रुपए की एक परियोजना, **नेशनल ऑटोमोटिव आरएण्डडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप)** से प्रारंभ करते हुए ऑटोमोटिव उपकर वित्तपोषण के माध्यम से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता, ऑटो अनुसंधान और विकास कुशलता के संग्राहक तथा सहयोगपूर्ण अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को पूरा करने और नैट्रिप केन्द्रों की गतिविधियों में सामंजस्य के लिए शीर्ष समन्वयक निकाय के रूप में **नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)** की स्थापना; हाल में अनुमोदित **नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020** के माध्यम से पर्यावरण पर ईंधन-उत्सर्जन प्रभाव को कम करने के साथ भविष्य में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह विभाग उपर्युक्त सभी नवीन पहलों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करता है और प्रत्येक वर्ष बजट में निधियों के पर्याप्त आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग सहित संबंधित स्टेकहोल्डरों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर सुझाव देता है। सरकार ने जेएनएनयूआरएम -II के तहत 10,000 बसें खरीदने का निर्णय भी लिया है।

*****